

सं० श्रो. वि./फरीदाबाद/20-84/9868.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मे. एस. जी. स्टील प्रा. लि., प्लाट नं. 6, सेक्टर 4, इण्डस्ट्रीयल कम हाऊर्सिंग इस्टेट, बल्लबगढ़ (फरीदाबाद) के श्रमिक श्री ग्रात्मा सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई ग्रौदोगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिये, अब, ग्रौदोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की घारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (बं) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की घारा 7(क) के अधीन ग्रौदोगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री ग्रात्मा सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. श्रो.वि./फरीदाबाद/20-84/9875.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मे. एस. जी. स्टील प्रा. लि., प्लाट नं० 6, सेक्टर 4, इण्डस्ट्रीयल कम हाऊर्सिंग इस्टेट, बल्लबगढ़ (फरीदाबाद) के श्रमिक श्री भूर्जा तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई ग्रौदोगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, ग्रौदोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की घारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की घारा 7(क) के अधीन ग्रौदोगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री भूर्जा की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. श्रो.वि./फरीदाबाद/20-84/9882.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मे. एस. जी. स्टील प्रा. लि., प्लाट नं. 6, सेक्टर 4, इण्डस्ट्रीयल कम हाऊर्सिंह इस्टेट, बल्लबगढ़ (फरीदाबाद) के श्रमिक श्री किशन लाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई ग्रौदोगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, ग्रौदोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की घारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की घारा 7(क) के अधीन ग्रौदोगिक अधिकरण हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री किशन लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

सं. श्रो.वि./फरीदाबाद/20-84/9889.—चूंकि राज्यपाल, हरियाणा की राय है कि मे० एस. जी. स्टील प्रा. लि., प्लाट नं. 6, सेक्टर 4, इण्डस्ट्रीयल कम हाऊर्सिंग इस्टेट, बल्लबगढ़ (फरीदाबाद) के श्रमिक श्री छतर पाल तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध कोई ग्रौदोगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इसलिए, अब, ग्रौदोगिक विवाद अधिनियम, 1947 की घारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की घारा 7(क) के अधीन ग्रौदोगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री छतर पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?